eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 08, August 2022

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमः महत्वाकांक्षी प्रयोग की शुरूआत

[1]डॉ0 अरविन्द कुमार शुक्ल
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी फ़तेहपुर

Abstract

प्रारंभ में भारत में कंप्यूटर का भी विरोध हुआ, लेकिन आज डिजिटल दुनिया के हर पल और हर दिन बदल रहे संदर्भों में कंप्यूटर हमारी दिनचर्या का मुख्य अंग बन गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकारी विभागों व सभी मंत्रालयों को देश की जनता से जोड़नें की भारत सरकार की एक अंतर–मंत्रालयी पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना है। इसके अंर्तगत डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एवं डिजिटल साक्षरता को लक्ष्य करके योजना को 2019 तक कार्यान्वयित करना है।

बीज शब्द – भारत में कंप्यूटर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, एक महत्वाकांक्षी प्रयोग एवं सरकार की एक पहल।

Introduction

सेवा प्रदाता और उपभोक्ता को लाभ हो सके ऐसे टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी एवं भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य सभी कमियों को भी दूर करना होगा। ब्रॉडबैंड हाईवे, सबको फोन की उपलब्धता, इंटरनेट तक सबकी पहुंच, इ–शासन (टेक्नालॉजी की मदद से शासन), ई–क्रांति (इलेक्ट्रानिक सेवाएं), सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी के जरिए रोजगार, भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 9 प्रमुख स्तंभ हैं।

डिजिटल इंडिया योजना पर कई कम्पनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई–कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। डिजिटल इंडिया मौजूदा योजनाओं में एक लाख करोड रुपये, नई योजनाओं और गतिविधियों में, 13 हजार करोड रुपये खर्च होंगे। 2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा, 2020 तक नेट जीरो आयात, 4

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 08, August 2022

लाख पब्लिक इंटरनेट प्वाइंट बनाना, 2.4 लाख स्कूलों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की व्यवस्था, आमलोगों के लिए वाई–फाई हॉट स्पॉट, 1.7 करोड़ लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग और रोजगार की संभावना सहित 1.7 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार व 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार, प्रदान करते हुए सभी प्रदेशों में सरकारों में इ–शासन को बढावा देना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकारी विभागों व सभी मंत्रालयों को देश की जनता से जोड़नें की भारत सरकार की एक एक अंतर–मंत्रालयी पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना है। इसके अंर्तगत डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एवं डिजिटल साक्षरता को लक्ष्य करके योजना को 2019 तक कार्यान्वयित करना है। सेवा प्रदाता और उपभोक्ता को लाभ हो सके ऐसे टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है।

डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी एवं भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य सभी कमियों को भी दूर करना होगा। ब्रॉडबैंड हाईवे, सबको फोन की उपलब्धता, इंटरनेट तक सबकी पहुंच, इ–शासन (टेक्नालॉजी की मदद से शासन), ई–क्रांति (इलेक्ट्रानिक सेवाएं), सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी के जरिए रोजगार, भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 9 प्रमुख स्तंभ हैं।

डिजिटल इंडिया योजना पर कई कम्पनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई–कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। डिजिटल इंडिया मौजूदा योजनाओं में एक लाख करोड रुपये, नई योजनाओं और गतिविधियों में, 13 हजार करोड रुपये खर्च होंगे।

2019 तक 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा, 2020 तक नेट जीरो आयात, 4 लाख पब्लिक इंटरनेट प्वाइंट बनाना, 2.4 लाख स्कूलों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की व्यवस्था, आमलोगों के लिए वाई–फाई हॉट स्पॉट, 1.7 करोड़ लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग और रोजगार की संभावना सहित 1.7 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार व 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार, प्रकान करते हुए सभी प्रदेशों में सरकारों में इ–शासन लागू करना है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 08, August 2022

यदि इस लेख का परिणाम या निष्कर्ष केवल एक वाक्य में कहें तो नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से डिजीटल क्षेत्र में साक्षर बनाना है और डिजीटल सशक्तिकरण होने के बाद कागजी काम कम हो जायेगा जैसे जमीन जायदाद का बैनामा, अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइन्टमेंन्ट, ओ0पी0डी0 की जानकारी, ई–लॉकर, ई–बस्ता, छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जनरेसन नेटवर्क का प्रयोग, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के साथ पुलिस स्टेशन, अस्पताल पर सीसीटीवी कैमरे तथा डाटा अपडेट होंगे इसके साथ शैक्षिक संस्थानों को वाई फाई हॉट स्पॉट से अपडेट करेंगे, कॉल सेन्टरों की संख्या बढेगी जिससे रोजगार भी बढेगा।

लोगों के दस्तावेजों जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्रों पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि का डिजीटल स्टोर करना इसके साथ ही भारत के सभी दूर दराज एवं पहाडी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर अनिवार्य होने से पूरे भारत में ई–गवर्नेंस की व्यवस्था होगी, लेकिन भारत को डिजीटल भारत बनाने में इस टैक्नोलॉजी की कुछ कमियॉ जैसे गोपनीयता की कमीं, नागरिक स्वायतता हनन, ई– सर्विलान्स हेतु संसदीय निगरानी की कमी, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी के साथ–साथ साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियॉ हैं, डिजीटल भारत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले इन सभी कमियों को दूर करते हुए प्रत्येक नागरिक को डिजीटल टैक्नोलॉजी में साक्षर बनाना है, जिससे देष का प्रत्येक नागरिक देष के विकास में अपना योगदान दे सकें। डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय भाषा से संचालित होने वाले तथा कम लागत में विशेष रूप से तैयार किये गए मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल–व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक अबाधित बिजली–आपूर्ति, सस्ती इंटरनेट–कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था करने से ग्रामीण भारत न केवल डिजिटल रूप से साक्षर होगा, बल्कि उसका सामाजिक–आर्थिक उत्थान भी संभव हो सकेगा। संस्थागत ऋण की व्यवस्था, JAM–ट्रिनिटी के उचित क्रियान्वयन से तथा भू–आलेखों के डिजिटलीकरण आदि के द्वारा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को अनौपचारिक से औपचारिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहायता मिल सकती है।

डिजिटल भुगतान आदि के समय होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिये सरकार को साइबर सुरक्षा मजबूत करनी चाहिये। एक सुरक्षित साइबर–स्पेस ग्रामीणों को डिजिटल व्यवहार के लिये प्रेरित करेगा। व्यापारिक गतिविधियों के दौरान डिजिटल भुगतान के लिये दुकानों,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 08, August 2022

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि पर POS- मशीनों (पॉइंट ऑफ सेल) आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिये इस योजना में और अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जिससे 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों के साथ ग्रामीण भारत में काम करने वाले 8.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और तकरीबन 18 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल साक्षर बनाकर लगभग पूरी ग्रामीण आबादी तक डिजिटलीकरण की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।

सन्दर्भः

1- अजय कुमार, डिजीटल इंडिया, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली, 2018
2- प्रदीप ठाकुर, भारत मे डिजीटल क्रान्ति, प्रभात पब्लिकेशन नई दिल्ली,2018।
3- www.digitalindia.gov.in
4- http://pib.nic.in/newsite/Print Release.aspx?relid=108926
5- वित्त मंत्रालय की वेवसाईट, भारत सरकार ।
6- कुरूक्षेत्र अंक अक्टूबर, 2014
7- 4- https://www.mygov.in/group/digital-india
8- 5- https://www.thebetterindia.com
9- 6- http://negd.gov.in